ऑयल इंडिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम) पंजीकृत कार्यालय : दुलियाजान, असम
Oil India Limited
(A Government of India Enterprise) Registered Office " Duliajan, Assam

प्लॉट. न. 19, सेक्टर 16-ए, नोएडा-201301 उत्तर प्रदेश
Plot No. : 19, Sector 16-A, Noida-201301, Uttar Pradesh
दूरभाष / Telephone : 0120-2488333-347 फैक्स / Fax : 0120-2488310

REF: OIL/SEC/NSE/BSE32-33/BUYBACK2018 March 14, 2019

To, The General Manager- Market Operations Department of Corporate Services **BSE Limited** Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street Fort, Mumbai 400 001, Maharashtra Ref Security Code: **533106**	To, The General Manager Listing Department **National Stock Exchange of India Limited** Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C-1, Block G, Bandra Kurla Complex, Bandra (East) Mumbai 400 051, Maharashtra

Sub: Post-Buyback Public Announcement pursuant to Regulation 24(vi) of the Securities and Exchange Board of India (Buy Back of Securities) Regulations, 2018 in relation to the buyback of equity shares of Rs 10 each of Oil India Limited ("Company") for an aggregate consideration not exceeding Rs 10,85,72,24,155 (Rupees One Thousand Eighty Five Crore Seventy Two Lakhs Twenty Four Thousand One Hundred and Fifty Five only) ("Buyback Offer")

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 24(vi) of the Securities and Exchange Board of India (Buy Back of Securities) Regulations, 2018, ("**Buyback Regulations**") the Company has made a Post-Buyback Public Announcement dated March 13, 2019 ("**Post Buyback Public Announcement**") for the buyback of not exceeding 5,04,98,717 (Five Crore Four Lakhs Ninety Eight Thousand Seven Hundred and Seventeen) fully paid-up equity shares of the Company of a face value of Rs 10 each at a price of Rs 215 (Rupees Two Hundred and Fifteen only) per equity share on a proportionate basis through the 'tender offer' route from the equity shareholders/beneficial owners of equity shares of the Company as on the record date i.e. Monday, December 3, 2018.

The Buyback Offer of the Company opened on Friday, February 15, 2019 and closed on Friday, March 1, 2019.

In accordance with the Buyback Regulations, the Company has made the Post Buyback Public Announcement in the following newspapers:

Publication	Language	Editions
Business Standard	English	All editions
Business Standard	Hindi	All editions
Dainik Assam	Assamese	Guwahati

A copy of the Post Buyback Public Announcement as published in the newspapers mentioned above is enclosed for your records.

It is requested to take the above information on record.

Thanking you,

Yours faithfully,
For Oil India Limited

(S.K. Senapati)
Company Secretary

Encl- As above

ब्रेक्सिट की अनिश्चितता पर ब्रिटेन में आईटी आउटसोर्सिंग बढ़ेगा

देवाशिष महापात्र
बेंगलूरु, 13 मार्च

यूरोपीय यूनियन से ब्रिटेन के बाहर होने पर अनिश्चितता

- विवेकाधीन खर्च से ग्राहकों के परहेज किए जाने के कारण बड़े अनुबंधों की संख्या कम
- यूरोपीय संघ से बाहर होने के ब्रिटेन के निर्णय के बाद ब्रिटेन का आउटसोर्सिंग बाजार 27 फीसदी घटकर 2018 में 2.5 अरब यूरो यानी करीब 2.9 अरब डॉलर का रह गया है

ब्रेक्सिट संबंधी अनिश्चितताओं के बावजूद ब्रिटेन में आईटी आउटसोर्सिंग अनुबंधों के कुल मूल्य में कमजोर आधार पर भी मामूली वृद्धि दिख सकती है। हालांकि इन अनुबंधों की प्रकृति में जबरदस्त बदलाव देखा जा रहा है क्योंकि बड़े अनुबंधों को कई टुकड़ों में विभिन्न वेंडरों को आउटसोर्स किए जा रहे हैं।

वैश्विक तकनीकी अनुसंधान एवं सलाहकार फर्म आईएसजी के अनुसार, यूरोपीय संघ से बाहर होने के ब्रिटेन के निर्णय के बाद ब्रिटेन का आउटसोर्सिंग बाजार 27 फीसदी घटकर 2018 में 2.5 अरब यूरो यानी करीब 2.9 अरब डॉलर का रह गया है। विश्लेषकों का मानना है कि कुल अनुबंध मूल्य में वृद्धि के बावजूद सभी बड़ी आईटी सेवा कंपनियों की वृद्धि को ब्रिटेन के कारोबार से झटका लग सकता है क्योंकि कई अरब वाले डिजिटल बदलाव वाले अनुबंध बाजार से नादारद हैं।

जैन कंसल्टिंग के पारीख जैन ने कहा, 'ग्राहक आउटसोर्सिंग संबंधी निर्णय ले रहे हैं लेकिन वे रणनीतिक परियोजना संबंधी निर्णय को टाल रहे हैं। सौदों के छोटे आकार से इस तथ्य का संकेत मिलता है।' उन्होंने कहा, 'लंबी अवधि की डिजिटल बदलाव वाली परियोजनाओं पर भारतीय आईटी उद्योग जबरदस्त दांव लगा रहा है ताकि राजस्व और मुनाफे को रफ्तार दिया जा सके। लेकिन लघु अवधि में अधिकतर बड़ी भारतीय आईटी कंपनियों को झटका लग सकता है क्योंकि ग्राहक अपने विवेकाधीन खर्च को फिलहाल टाल रहे हैं।'

आईएसजी के पूर्वानुमान के अनुसार, इस साल खंडित बाजार की प्रवृत्ति दिख रही है जहां व्यक्तिगत अनुबंधों की संख्या में करीब 5 फीसदी की वृद्धि होगी। जून 2016 में ब्रेक्सिट के लिए मतदान के बाद ब्रिटेन का पारंपरिक आउटसोर्सिंग बाजार पिछले तीन वर्षों में घटा है। मतदान से पहले प्रति तिमाही औसत आउटसोर्सिंग अनुबंध का आकार करीब 90 करोड़ डॉलर के दायरे में रहा है।

फिलहाल यूरोपीय संघ से बाहर होने का जोखिम काफी अधिक है क्योंकि देश को 29 मार्च की अंतिम समय-सीमा तक पहुंचना है। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टरीसा में द्वारा इस मुद्दे पर आमराय बनाने की कई बार कोशिश की गई लेकिन कोई ठोस निर्णय होना अभी बाकी है। विश्लेषकों का मानना है कि ब्रिटेन की प्रधानमंत्री के प्रस्ताव को वहां के पार्लियामेंट में ठुकराए जाने से देश धीरे-धीरे कठिन ब्रेक्सिट की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में यूरोपीय संघ के साथ व्यापार की शर्तें अनुकूल नहीं रहेंगी जिससे काफी हद तक ब्रिटेन में कारोबारी प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित होगी।

लंदन की फर्म ओवम रिसर्च की वरिष्ठ विश्लेषक हंसा आयंगर ने कहा, 'ब्रेक्सिट के कारण बाजार में काफी चिंता है क्योंकि ऐसा नहीं लग रहा है कि ब्रिटेन यूरोपीय संघ से बाहर होने के साथ ही अनुकूल व्यापार शर्तों के लिए बातचीत करने जा रहा है।'

भारतीय आईटी उद्योग की टाटा कंसल्टैंसी सर्विसेज (टीसीएस), इन्फोसिस, विप्रो और एचसीएल टेक्नोलॉजिज सहित सभी चार प्रमुख कंपनियों का ब्रिटेन के बाजार में काफी निवेश है।

समय से पहले टाटा स्टील बीएसएल ने चुकाया कर्ज

वित्त वर्ष के पहले 9 महीने में कंपनी का एबिटा बढ़कर 3,013 करोड़ रुपये पर पहुंचा

दिलीप सत्पथी
भुवनेश्वर, 13 मार्च

टाटा स्टील की तरफ से 54 लाख टन क्षमता वाली भूषण स्टील के अधिग्रहण से इस कंपनी की किस्मत चमक गई है और कंपनी 3,000 करोड़ रुपये के कर्ज का भुगतान समय से पहले करने में सक्षम हो गई। इसके लिए कंपनी ने इकाई में बढ़ते नकदी प्रवाह का सहारा लिया।

सूत्रों ने कहा, टाटा स्टील के प्रबंधन के तहत पिछले 10 महीने में भूषण स्टील के संयंत्र के वित्तीय व अन्य प्रदर्शन में भारी सुधार के चलते यह मुमकिन हो पाया है। टाटा स्टील की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक बमनीपाल स्टील लिमिटेड (बीएनपीएल) ने मई 2018 में दिवालिया संहिता के तहत 32,500 करोड़ रुपये में भूषण स्टील लिमिटेड का अधिग्रहण किया था।

इस अधिग्रहण के वित्त पोषण के लिए टाटा स्टील ने बीएनपीएल के जरिए 16,500 करोड़ रुपये का कर्ज सुनिश्चित किया और अंतर-कंपनी कर्ज के जरिए 18,500 करोड़ रुपये दिए। इस तरह से कुल 35,000 करोड़ रुपये दिए गए, जिसमें से कंपनी ने 3,000 करोड़ रुपये का भुगतान समय से पहले कर दिया है। सूत्रों ने यह जानकारी दी।

इसके अलावा टाटा स्टील बीएसएल (अधिग्रहीत इकाई का नया नाम) ने अल्पावधि वाले अधिग्रहण कर्ज के बदले लंबी अवधि का 15,500 करोड़ रुपये का कर्ज दिया है, जिसने कंपनी के जोखिम प्रोफाइल में सुधार किया है।

15,500 करोड़ रुपये की यह रकम ब्रिज लोन के बदले नए कर्ज का एक हिस्सा है। बाकी 35,000 करोड़ रुपये के कर्ज को तरजीही शेयर में बदला जाएगा, जिसके लिए शेयरधारकों की मंजूरी इस हफ्ते मिल गई है।

इस यूनिट की क्रेडिट रेटिंग केयर रेटिंग की तरफ से लंबी अवधि के लिए बढ़ाकर एए की गई है जबकि अल्पावधि के लिए ए 1 प्लस, जिससे वित्तीय लागत घटने की संभावना है।

कंपनी का एबिटा वित्त वर्ष 2018 के पहले नौ महीने के 1,442 करोड़ रुपये से बढ़कर इस साल समान अवधि में 3,013 करोड़ रुपये पर पहुंच गई, वहीं एबिटा मार्जिन वित्त वर्ष 2019 में अब तक पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 8 फीसदी बढ़ा है।

कंपनी का कारोबार मौजूदा वित्त वर्ष के पहले नौ महीने में बढ़कर 15,374 करोड़ रुपये पर पहुंच गया, जो एक साल पहले के 12,908 करोड़ रुपये के मुकाबले 19 फीसदी ज्यादा है।

टाटा स्टील बीएसएल अभी पूर्ण उत्पादन क्षमता पर पहुंचने की कोशिश में जुटी है। इसमें बढ़ोतरी का अनुमानित समय 24 महीने होगी। कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, हम संयंत्र के रखरखाव व सुरक्षा मानकों में सुधार पर भी ध्यान दे रहे हैं, जिससे उत्पादन में इजाफा करने में मदद मिलेगी।

वित्त वर्ष 2019 के पहले नौ महीने में हॉट मेटल का उत्पादन 31 लाख टन रहा और कंपनी इस साल पहली बार हॉट मेटल का उत्पादन 40 लाख टन के पार ले जाने की राह पर है। इसी तरह कच्चे स्टील का उत्पादन 31 लाख टन रहा जबकि हॉट रोल्ड कॉयल का उत्पादन 29 फीसदी रहा, जो उत्पादन में क्रमशः 14 फीसदी व 16 फीसदी की बढ़ोतरी दर्शाता है।

एनसीएलएटी : आरकॉम मामले में फैसला सुरक्षित

आशिष आर्यन
नई दिल्ली, 13 मार्च

आरकॉम 260 करोड़ रुपये के टैक्स रिफंड का इस्तेमाल एरिक्सन को 550 करोड़ रुपये के बकाए के भुगतान में करना चाहती है

नैशनल कंपनी लॉ अपील ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) ने बुधवार को आरकॉम की उस याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें कंपनी ने एक खाते में रखी गई टैक्स रिफंड के 260 करोड़ रुपये जारी करने की मांग की थी। भारतीय स्टेट बैंक समेत कंपनी के करीब 40 लेनदारों ने आरकॉम की उस योजना का विरोध किया था जिसके तहत आरकॉम ने एरिक्सन को भुगतान में इसके इस्तेमाल की अनुमति मांगी थी। लेनदारों ने कहा था कि एरिक्सन को भुगतान अन्य स्रोत से किया जाना चाहिए। इस खाते के ट्रस्टी बैंक हैं।

बुधवार को एसबीआई ने दोहराया कि टैक्स रिफंड पर पहला हक उसका है, जो खाते में आए हैं। एसबीआई की अगुआई वाले लेनदारों के संयुक्त फोरम ने मंगलवार को भी कहा था कि आरकॉम की संपत्ति बिक्री से 37,000 करोड़ रुपये की रिकवरी में नाकामी का ठीकरा उन पर नहीं फोड़ा जाना चाहिए।

एसबीआई के वकील नीरज कृष्ण कौल ने कहा, यह इसलिए नाकाम हुआ क्योंकि जियो ने आरकॉम के पिछले कर्ज का भुगतान करने से मना कर दिया। अब आरकॉम को एरिक्सन के भुगतान के लिए प्रावधान करना है, चाहे सौदा हो या न हो।

बुधवार को एनसीएलएटी में हुई सुनवाई में आरकॉम व एसबीआई के वकीलों के बीच दलीलों का दौर जारी रहा। आरकॉम ने आरोप लगाया कि एसबीआई ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर कहा था कि एनसीएलएटी से मामला हस्तांतरित होना चाहिए क्योंकि अपील ट्रिब्यूनल इस मामले में सर्वोच्च्च न्यायालय के निर्देशों की व्याख्या ठीक से नहीं कर रहा है। आरकॉम के वकील कपिल सिब्बल ने कहा, बैंक हमें सूचित किए बिना सर्वोच्च न्यायालय चला गया। एसबीआई ने हालांकि कहा कि वह अपने अधिकार को सुरक्षित करने के लिए ही सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा था।

सेबी ने दूर कीं असूचीबद्धता नियमों की खामियां

सुंदर सेतुरामन
मुंबई, 13 मार्च

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने नए गैर-सूचीबद्धता नियमों की बड़ी खामियां दूर की है। बुधवार को बाजार नियामक ने गैर-सूचीबद्धता नियों में संशोधन किया। इसके तहत अगर रिवर्स बुक बिल्डिंग के तहत तय कीमत स्वीकार न हो तो अधिग्रहण करने वाले को जवाबी पेशकश की अनुमति मिली है।

सेबी के नियमों के मुताबिक, अधिग्रहण करने वालों की तरफ से जवाबी पेशकश की स्टॉक एक्सचेंजों के जरिये सार्वजनिक घोषणा बोली प्रक्रिया समाप्त होने के दो कार्यदिवस के भीतर होना चाहिए। इसके अतिरिक्त जवाबी पेशकश से जुड़ी सार्वजनिक घोषणा रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रक्रिया समाप्त होने के चार कार्यदिवस के भीतर उसी अखबार में प्रकाशित होनी चाहिए जहां मूल रूप से रिवर्स बुक बिल्डिंग की घोषणा की गई थी।

जवाबी पेशकश की घोषणा के 10 कार्यदिवस के भीतर शेयरधारकों को अपने शेयर वापस लेने का विकल्प मिलना चाहिए। जवाबी पेशकश का पत्र रिवर्स बुक बिल्डिंग की समाप्ति के चार दिन के भीतर भेजा जाना चाहिए और जवाबी पेशकश इसकी घोषणा के सात कार्यदिवस के भीतर खोला जाना चाहिए। सेबी ने एक परिपत्र में यह जानकारी दी।

जवाबी पेशकश की बोली पांच कार्यदिवस के लिए खुली रहेगी। रकम का भुगतान और इक्विटी शेयर की वापसी जवाबी पेशकश की समाप्ति के 10 कार्यदिवस के भीतर होनी चाहिए।

लिंडे इंडिया की गैर-सूचीबद्धता बोली के दौरान नियमों की ये खामियां सामने आई। विशेषज्ञों ने कहा कि एमएनसी फर्म की गैर-सूचीबद्धता जवाबी पेशकश की प्रक्रिया पर अस्पष्टता के चलते नाकाम हुई। लिंडे इंडिया के प्रर्वतकों ने रिवर्स बुक बिल्डिंग की प्रक्रिया के जरिए तय कीमत को ठुकराने का फैसला लिया।

पाइपलाइन के लिए शुल्क दर में इजाफा

एजेंसियां
नई दिल्ली, 13 मार्च

तेल नियामक पीएनजीआरबी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के पूर्वी अपतटीय केजी डी-6 से गैस ग्राहकों तक पहुंचाने वाली पाइपलाइन के लिए शुल्क में 1 अप्रैल से 37 फीसदी की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। अंतिम शुल्क आदेश में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) ने 12 मार्च के आदेश में कहा है कि ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन से प्राकृतिक गैस परिवहन की लागत 1 अप्रैल से प्रति 10 लाख ब्रिटिश थर्मल यूनिट (एमएमबीटीयू) 71.66 रुपये होगी। फिलहाल यह 52.33 रुपये प्रति यूनिट (एमएमबीटीयू) है। शुल्क की मौजूदा दर 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2019 के लिए है। नई दर, पाइपलाइन की परिचालक ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन लिमिटेड की ओर से की गई मांग के लगभग आधे के बराबर है।

कंपनी ने 1 अप्रैल 2018 से शुल्क दर बढ़ाकर 151.84 रुपये प्रति 10 लाख ब्रिटिश थर्मल यूनिट करने की मांग की थी।

शुल्क दर में वृद्धि से उर्वरक के साथ-साथ सीएनजी के दाम बढ़ेंगे, जहां गैस आंध्र प्रदेश में काकीनाड़ा से गुजरात के भड़ूच तक गई पाइपलाइन से ली जाती है। पीएनजीआरबी ने अपने 49 पृष्ठ के आदेश में लागत आकलन तथा अन्य मानदंडों के आधार पर शुल्क दरें निर्धारित की हैं। शुल्क में सूचना तथा आंकड़ों के ऑडिट के आधार पर संशोधन किया जाएगा।

मूल रूप से ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन ने 1 अप्रैल 2009 से शुल्क की दर 55.91 प्रति एएमबीटीयू करने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन पीएनजीआरबी ने 52.33 रुपये प्रति एमएमबीटीयू का शुल्क तय किया था।

कंपनी ने अक्टूबर 2017 में पाइपलाइन के लिए 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2034 तक अंतिम शुल्क 78.22 रुपये प्रति यूनिट रखने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन पीएनजीआरबी की तरफ से स्पष्टीकरण मांगे जाने के बाद ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन ने कहा था कि 2017 तक शुल्क 52.23 प्रति एमएमबीटीयू होगा और 2018-19 से 2035-36 तक शुल्क 151.84 रुपये होगा।

रोजगार के लिए जरूरी कौशल नहीं रखते भारतीय

प्रौद्योगिकी कंपनी आईबीएम की प्रमुख गिन्नी रोमेटी ने कहा है कि भारतीयों के पास जरूरी कौशल का अभाव है, जिसकी वजह से उन्हें नौकरी नहीं मिल रही। जबकि दूसरी तरफ नए जमाने के रोजगार अधिक मात्रा में सृजित हो रहे हैं। उन्होंने सभी को डिग्री से इतर शिक्षा प्राप्त करने की जरूरत पर जोर दिया। कुल 180 अरब डॉलर के घरेलू सॉफ्टवेयर उद्योग में प्रत्यक्ष रूप से 40 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है। आईबीएम की चेयरमैन, अध्यक्ष और मुख्य कार्याधिकारी रोमेटी ने कहा कि यह वैश्विक समस्या है और केवल भारत तक सीमित नहीं है। कंपनी के एक सम्मेलन के दौरान उन्होंने बुधवार को कहा, भारत में भी वहीं मुद्दे हैं। रोजगार सृजित हो रहे हैं लेकिन उसके मुताबिक काबिलियत या कौशल नहीं है। उन्होंने यह बात ऐसे समय कही है जब बताया जाता है कि इंजीनियरिंग की डिग्री वाले लाखों युवाओं के पास रोजगार नहीं है। *भाषा*

APPOINTMENTS

IDBI BANK

विज्ञापन संख्या 5 / 2018-19

चार्टर्ड अकाउंटेंट की भर्ती के लिए विज्ञापन

उप महा प्रबन्धक (3), सहायक महा प्रबन्धक (5) और प्रबन्धक (32) पद के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं.

आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तारीख 25 मार्च 2019 है.

जानकारी (आयु एवं कार्य के अनुभव के संबंध में विस्तृत पात्रता मानदंड तथा संबंधित अनुदेशों के लिए) और आवेदन करने के लिए कृपया बैंक की वेबसाइट **www.idbi.com** देखें.

कॉर्पोरेट कार्यालय : आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई - 400005. टेलीफ़ोन : 022-22189111, वेबसाइट : **www.idbi.com**

नोट : आईडीबीआई बैंक के पास किसी/ कोई भी आवेदन पत्र को, कुछ भी कारणवश से, स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित हैं.

ऑयल इंडिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
Oil India Limited
(A Government of India Enterprise)

CIN: L11101AS1959GOI001148
Registered Office: Duliajan, Distt. Dibrugarh, Assam - 786 602, India
Corporate Office: Plot No. 19, Sector 16A, Noida - 201 301, Uttar Pradesh, India
Contact Person: Shri S. K. Senapati, Company Secretary and Compliance Officer
Tel: +91 (120) 241 9000 | **Fax:** +91 (120) 248 8310
Email: complianceofficer@oilindia.in | **Website:** www.oil-india.com

POST BUYBACK PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR THE ATTENTION OF EQUITY SHAREHOLDERS/BENEFICIAL OWNERS OF EQUITY SHARES OF OIL INDIA LIMITED

This post buyback public announcement (the "Post Buyback Public Announcement") is being made pursuant to the provisions of Regulation 24(vi) of the Securities and Exchange Board of India (Buy Back of Securities) Regulations, 2018 (the "Buyback Regulations"). This Post Buyback Public Announcement should be read in conjunction with the Public Announcement dated November 20, 2018 which was published on November 21, 2018 (the "Public Announcement") and the Letter of Offer dated February 5, 2019 (the "Letter of Offer"). The terms used but not defined in this Post Buyback Public Announcement shall have the same meaning as assigned to such terms in the Public Announcement and the Letter of Offer.

1. THE BUYBACK OFFER

1.1 Oil India Limited (the "**Company**") had announced the Buyback of not exceeding 5,04,98,717 (Five Crore Four Lakhs Ninety Eight Thousand Seven Hundred and Seventeen) fully paid-up equity shares of face value of ₹ 10 each ("**Equity Shares**") from all the equity shareholders/beneficial owners of Equity Shares as on the record date (i.e. Monday, December 3, 2018), on a proportionate basis, through the "**Tender Offer**" route at a price of ₹ 215 (Rupees Two Hundred and Fifteen only) per Equity Share payable in cash for an aggregate consideration not exceeding ₹ 10,85,72,24,155 (Rupees One Thousand Eighty Five Crore Seventy Two Lakhs Twenty Four Thousand One Hundred and Fifty Five only) ("**Buyback Offer Size**"). The Buyback Offer Size represents 5.00% and 5.01% of the aggregate of the fully paid-up equity share capital and free reserves as per the audited standalone and consolidated financial statements of the Company for the financial year ended March 31, 2018, respectively (the last audited financial statements available as on the date of the Board Meeting approving the Buyback) and is within the statutory limits of 10% of the aggregate of the fully paid-up equity share capital and free reserves as per standalone audited financial statements of the Company as per the provisions of the Companies Act, 2013 and the Buyback Regulations. The number of Equity Shares bought back in the Buyback constitutes 4.66% of the post Buyback equity share capital of the Company.

1.2. The Company has adopted Tender Offer route for the purpose of Buyback. The Buyback was implemented using the "Mechanism for acquisition of shares through Stock Exchange" notified by SEBI vide circular CIR/CFD/POLICYCELL/1/2015 dated April 13, 2015 read with the circular CFD/DCR2/CIR/P/2016/131 dated December 9, 2016, as may be amended from time to time ("**SEBI Circulars**"), notice number 20170202-34 dated February 2, 2017 from BSE and following the procedure prescribed in the Companies Act, 2013 and the Buyback Regulations.

1.3 The Buyback Offer opened on Friday, February 15, 2019 and closed on Friday, March 1, 2019.

2. DETAILS OF BUYBACK

2.1. The total number of Equity Shares bought back under the Buyback Offer are 5,04,98,717 (Five Crore Four Lakhs Ninety Eight Thousand Seven Hundred and Seventeen) Equity Shares at a price of ₹ 215 (Rupees Two Hundred and Fifteen only) per Equity Share.

2.2 The total amount utilized in the Buyback of Equity Shares is ₹ 10,85,72,24,155 (Rupees One Thousand Eighty Five Crore Seventy Two Lakhs Twenty Four Thousand One Hundred and Fifty Five Only) excluding filing fees payable to the SEBI, Stock Exchanges fees, advisors fees, turnover charges, public announcement publication expenses, printing and dispatch expenses, transaction costs viz. brokerage, applicable taxes such as securities transaction tax, service tax, stamp duty, etc.

2.3 The Registrar to the Buyback i.e. Karvy Fintech Private Limited *(formerly KCPL Advisory Services Private Limited)* (the "**Registrar**") considered 26,421 valid bids for 9,34,15,649 (Nine Crore Thirty Four Lakhs Fifteen Thousand Six Hundred and Forty Nine only) Equity Shares in response to the Buyback, resulting in the subscription of approximately 1.85 times the maximum number of shares proposed to be bought back.

The details of valid bids received by the Registrar in the Buyback Offer are as follows:

Category of Investor	No. of Equity Shares reserved in Buyback	No. of Valid Bids	Total Equity Shares Validly tendered	% Response
General category	4,29,23,909	1,541	8,53,90,309	198.93
Reserved category	75,74,808	24,880	80,25,340	105.95
Total	**5,04,98,717**	**26,421**	**9,34,15,649**	**184.99**

2.4. All valid bids have been considered for the purpose of Acceptance in accordance with the Buyback Regulations and Paragraph 19 of the Letter of Offer. The communication of acceptance/rejection has been dispatched by the Registrar to respective Eligible Shareholders on Tuesday, March 12, 2019.

2.5 The settlement of all valid bids was completed by the Clearing Corporation on Tuesday, March 12, 2019. For Demat Equity Shares accepted under the Buyback, the Eligible Shareholder will receive funds payout in their settlement bank account from the Clearing Corporation and in case of physical shares, the Clearing Corporation will release the funds to the Shareholder Broker as per secondary market payout mechanism. If Eligible Shareholder bank account details were not available or if the funds transfer instruction were rejected by RBI/respective bank, due to any reason, then such funds were transferred to the concerned Shareholder Broker for onward transfer to their respective Eligible Shareholder.

2.6 Demat Equity Shares accepted under the Buyback have been transferred to the Company's demat escrow account on Tuesday, March 12, 2019. The unaccepted demat Equity Shares have been returned to respective Shareholder/Shareholder Brokers/custodians by the Clearing Corporation on Tuesday, March 12, 2019. For Equity Shares tendered in physical form, the share certificates in respect of unaccepted Equity Shares are being dispatched to the registered address of the respective Eligible Shareholders by the Registrar/Company.

2.7 The extinguishment of 5,04,98,717 Equity Shares accepted under the Buyback comprising of 5,04,96,853 Equity Shares in dematerialized form and 1,864 Equity Shares in physical form, is currently under process and shall be completed by Tuesday, March 19, 2019. The Company and its directors accept full responsibility for the information contained in this Post Buyback Public Announcement and also accept responsibility for the obligations of the Company laid down under the Buyback Regulations.

3. CAPITAL STRUCTURE AND SHAREHOLDING PATTERN

3.1. The capital structure of the Company, pre and post Buyback Offer is as under:

(Equity Shares have a face value of ₹ 10 each)

Particulars	Pre Buyback		Post Buyback#	
	No. of Equity Shares	Amount (₹ in crore)	No. of Equity Shares	Amount (₹ in crore)
Authorized share capital	2,00,00,00,000	2,000.00	2,00,00,00,000	2,000.00
Issued, subscribed and paid up share capital	1,13,49,03,911	1,134.90	1,08,44,05,194	1,084.41

 # Subject to extinguishment of 5,04,98,717 Equity Shares

3.2. The details of the Shareholders/beneficial owners from whom Equity Shares exceeding 1% of the total Equity Shares bought back have been accepted for the Buyback Offer are as mentioned below:

S. No.	Name of the Shareholders	No. of Equity Shares accepted under the Buyback Offer	Equity Shares accepted as a % of total Equity Shares bought back	Equity Shares accepted as a % of total post Buyback Equity Shares
1.	The President of India acting through Ministry of Petroleum and Natural Gas, Government of India	3,35,63,696	66.46	3.10
2.	ICICI Prudential Life Insurance Company Limited	15,23,319	3.02	0.14

3.3. The shareholding pattern of the Company pre-Buyback (as on Record Date i.e. Monday, December 3, 2018) and post Buyback, is as under:

Particulars	Pre Buyback		Post Buyback^*	
	No. of Equity Shares	% of the existing Equity Share Capital	No. of Equity Shares	% of the post Buyback Equity Share Capital
Promoter	75,05,48,332	66.13	68,36,64,235	63.05
Foreign Investors (including Non Resident Indians, FIIs, FPIs and Foreign Mutual Funds	4,86,53,006	4.29	40,07,40,959	36.95
Financial Institutions/Banks/Mutual Funds promoted by Banks/Institutions	16,51,47,990	14.55		
Other (public, public bodies corporate etc.)	17,05,54,583	15.03		
Total	**1,13,49,03,911**	**100.00**	**1,08,44,05,194**	**100.00**

^In addition to the acceptance of 3,35,63,696 Equity Shares from the Promoter in the Buyback Offer, the post-Buyback shareholding of the Promoter also takes into account the transfer by the Promoter of 3,33,20,401 Equity Shares in relation to the CPSE ETF Scheme to the account of Reliance Nippon Life Asset Management Limited on December 4, 2018.

**Subject to extinguishment of 5,04,98,717 Equity Shares.*

4. MANAGER TO THE BUYBACK OFFER

SBI Capital Markets Limited

SBI CAPITAL MARKETS LIMITED
202, Maker Tower E, Cuffe Parade, Mumbai 400 005
Contact person: Mr. Janardhan Wagle/Mr. Aditya Deshpande
Tel: +91 (22) 2217 8300; **Fax**: +91 (22) 2218 8322
Email: oilbuyback2018@sbicaps.com; **Website**: www.sbicaps.com
SEBI Registration Number: INM000003531
Validity Period: Permanent Registration
CIN: U99999MH1986PLC040298

5. DIRECTORS' RESPONSIBILITY

As per Regulation 24(i)(a) of the Buyback Regulations, the Board of Directors of the Company accept full responsibility for the information contained in this Post Buyback Public Announcement and confirm that the information in this Post Buyback Public Announcement contains true, factual and material information and does not contain any misleading information.

For and on behalf of the Board of Directors of
OIL INDIA LIMITED

Sd/-	Sd/-	Sd/-
(Shri Utpal Bora)	(Shri Pramod Kumar Sharma)	(Shri S. K. Senapati)
Chairman & Managing Director	Director (Operations)	Company Secretary and Compliance Officer
(DIN: 07567357)	(DIN: 07194463)	(FCS: 2898)

Date : March 13, 2019
Place : Noida

PRESSMAN

Parle infuses fresh life into 2 legacy brands

Krackjack and Monaco get a brand refresh as the company looks to carve a wider niche in the crackers market and build its millennial credentials

T E NARASIMHAN
Chennai, 13 March

At 50 and 75 years, Krackjack and Monaco are among the oldest brands in the Parle pack. And for that reason alone, one would assume, unlikely contenders for millennial attention. However the two brands are leading the company's charge into the demographic and driving Parle's efforts to expand its footprint in the ₹5000-crore-plus market for crackers.

Krackjack valued at ₹800 crore and Monaco around ₹550 crore (A C Nielsen estimates as provided by industry) have seen a concerted marketing push in recent months. New flavours and packaging apart, the company is also working on an independent identity for the two. The company says it is high time that these brands stand out, sharing their own independent spot of the sky under the Parle banner. The two will also see more brand extensions, while some existing ones will get a fresh coat of marketing gloss.

The cracker segment that both Monaco and Krackjack are part of, is estimated to be about 15 per cent of the ₹35,000 crore biscuit market. Parle has four brands in the mix here but these are the big two, which give it nearly 28 per cent market share. Britannia is market leader while Parle holds the second spot.

(*Top*) The new campaigns for Krackjack and Monaco (*right*) have been released in 11 languages so far

Today biscuits as a category is growing at around 12 per cent, in that cookies and cream biscuits are growing at around 16-18 per cent, crackers clock around 9-10 per cent. Mayank Shah, senior category head at Parle, believes that brands have been lethargic in developing the segment so far. It has not seen any major launches in recent years, he says. Parle wants to change that. It has launched two new variants, KrackJack Butter Masala and Monaco Pizza in recent weeks.

> **"Old brands like Krackjack or Monaco are fixed in their ways, you don't expect them to be different. Such extensions create an excitement around the brand"**
> AMBI PARAMESWARAN
> Founder, Brand-Building.com

Ambi Parameswaran, brand strategist and founder of Brand-Building.com says that extensions are a tried and tested way of re-energising brands. "Old brands like KrackJack or Monaco are fixed in their ways, you don't expect them to be different. Such extensions create an excitement around the brand," he adds.

Keeping consumers interested is a challenge and extensions help do that, but Parameswaran says, one must not look at such exercises as a means to multiply sales. Extensions may account for five per cent of the total sales but the important thing is that they can sell the mother product. "It gives consumers the faith that their brand is an exciting brand, interesting things are happening. Also extensions help a brand try and test new price points. They work in many ways, but the only thing is that you need to keep them under control. If you have unrealistic expectations, then a brand can fall flat. If one expects sales, growing at say five per cent per annum, to jump 20 per cent after such launches, it will go wrong," he adds.

Parle believes that the crackers category has not seen too many experiments in the past and it hopes to drive the buzz around its brands with two new variants to begin with, available in different sizes and at two price points, ₹10 and ₹25.

Parle is rolling out a multimedia campaign across print, digital and television for the two brands. The TVCs will be released in 11 languages, including Hindi, English, Marathi, and Tamil and will be followed up with a digital campaign.

The brands' main customers are in the age group of 15-25 years for Krackjack and 15-35 years, for Monaco. The company says it will first target markets with population over five lakh and in the second phase, in less than 24 months, move to towns with one lakh plus population. This, says Shah, is a different move compared to the usual strategy of going to the markets with over 10 lakh population in the initial stage.

The company expects the two new additions would add around 15-20 per cent to the KrackJack and Monaco business in the first year of launch.

▸ FROM PAGE 1

RBI puts auditors of banks on notice

It will be a departure from the current practice of engaging with auditors once they have signed off on the annual accounts of banks and the long-form audit report. The central bank has basically given a new life to the largely discontinued practice of quarterly discussions with banks – it is now to be with auditors.

The trigger for the new format is the huge variance seen in bank-declared non-performing assets (NPAs) and what's subsequently been thrown up in the RBI's inspection reports, besides less-than-adequate compliance and governance standards in banks. These issues had come to the fore when the central bank undertook its asset quality review (AQR), and are to be addressed now within the matrix of a formal interactive structure between banks' auditors and the RBI.

The fount of the current narrative started when auditors were caught flat-footed after the AQR was initiated in December 2015, and the central bank's April 18, 2017 circular on disclosures on provisioning. The latter asked banks to disclose in the "Notes to Accounts" of their financial statements the additional provisioning requirements exceeding 15 per cent of the published net profits for the reference period; or the additional gross NPAs (identified by the RBI) exceeding 15 per cent of the published incremental gross NPAs for the reference period -- or both. When the RBI made its displeasure clear to auditors on the variance in dud loans, they apprised the regulator of the fact that from the time the AQR was announced and the circular on divergence in provisioning was issued, two rounds of bank inspections had been undertaken by Mint Road. While cognisance had been taken of the AQR when they audited banks at end-March 2016, the exercise had been interpreted as being "subjective" to the extent the RBI decided which accounts were to be classified as NPAs.

Auditors had gone by Mint Road's general guidelines on income recognition and asset classification even as they took AQR's observations on board. "It was all lost in the English of the communication", said a senior partner at an audit firm who did not wish to be named, adding: "In any case, our point was we are not inspectors but auditors, and don't get to forensically know if there was systemic fund diversion or round-tripping by borrowers."

RBI to swap $5 bn with banks to aid liquidity

"Banks may not have adequate collateral to pledge to borrow from the RBI because of high SLR (statutory liquidity ratio) and LCR (liquidity coverage ratio) requirement, and so, this liquidity support through dollar purchase would be needed to partially meet the requirement," said Soumyajit Niyogi, associate director, India Ratings and Research. Another senior bond trader said this kind of liquidity management was often done by the RBI and banks. However, it was not in a large scale, so it was never notified.

The central bank said the swap facility is part of its "liquidity management toolkit" and would be to meet the durable liquidity needs of the system. "The swap is in the nature of a simple buy/sell foreign exchange swap from the Reserve Bank's side. A bank shall sell US dollars to the RBI and simultaneously agree to buy the same amount of US dollars at the end of the swap period," the central bank said.

"The US dollar amount mobilised through this auction would also reflect in the RBI's foreign exchange reserves for the tenor of the swap while also reflecting in RBI's forward liabilities," the RBI said. This means the foreign exchange reserve will see a bump of $5 billion, while the RBI's forward sell position will also go up by $5 billion. The RBI will buy dollar from banks, only to sell it three years down the line to banks. At present, the RBI has a net sale position of $3 billion in the forwards segment. "The market participants would be required to place their bids in terms of the premium that they are willing to pay to the Reserve Bank for the tenor of the swap, expressed in paisa terms up to two decimal places. The auction cut-off would be based on the premium," the RBI said in its statement.

Govt considering ₹13K-cr bailout package for BSNL

The firm's debt stands at ₹13,000 crore. The debt-laden company has failed to secure bank loans in the past two years. The overall debt of the telecom sector is estimated at over ₹6 trillion.

The bailout proposal under consideration of the DoT will require approval from the Digital Communications Commission (DCC), the telecom sector's topmost decision-making body. The government is of the view that telecom is a strategic sector and public sector presence is a must. With the model code of conduct for the Lok Sabha polls in place, the decision to revive the sick PSU may not come through anytime soon. However, an official told Business Standard that the deliberations were on regarding a revival package as "we cannot let our company sink".

Revival packages for BSNL and MTNL were discussed in the meeting of the DCC in February. The suggestions by the firms included the conversion of debt into sovereign guarantee, pay revision and subsequent voluntary retirement. BSNL sought 4G spectrum across India through an equity infusion of ₹7,000 crore. MTNL suggested converting its ₹20,000 crore debt into sovereign and surrendering 3G spectrum. A voluntary retirement package based on the Gujarat model is in the works and the DoT has proposed that the package should be funded by a bond issue over 10 years, which will bring down cost implications for the government.

Azim Premji raises philanthropic contribution to $21 bn

All this in partnership with state governments - this fieldwork is in Karnataka, Uttarakhand, Rajasthan, Chhattisgarh, Puducherry, Telangana, and Madhya Pradesh, along with some work in the northeastern states. The Foundation's field strategy focuses on creating and scaling up a network of institutions at the district and state levels, to contribute to improvement in the school education system. It has also set up the Azim Premji University in Bengaluru. Established with the official aim of developing of professionals in the domains of education and related areas.

The initiative to support other not-for-profits with multi-year grants was started in 2014, enabling expansion to domains other than education. The grants support efforts for tangible improvement in the lives of the poor and marginalised sections. The grants have gone to a little over 150 organisations in a range of domains. The Foundation said it expected to significantly expand its activities over the coming years.

BS SUDOKU # 2690

	5	8	3					7
		2					9	
			8		1	2		
			4	1			7	5
9	4			3	8			
		6	2		3			
	9					8		
2					6	7	1	

SOLUTION TO #2689

3	9	4	7	8	1	6	5	2
1	6	5	2	9	4	3	7	8
8	2	7	5	3	6	9	4	1
9	7	6	1	5	8	4	2	3
2	8	3	6	4	7	1	9	5
4	5	1	9	2	3	7	8	6
5	4	8	3	1	9	2	6	7
6	3	2	4	7	5	8	1	9
7	1	9	8	6	2	5	3	4

Vary Hard: ★★★★★

Solution tomorrow

HOW TO PLAY

Fill in the grid so that every row, every column and every 3x3 box contains the digits 1 to 9

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India
अच्छे लोग, अच्छा बैंक Good people to bank with

Bhat Bazar Branch
Anant Deep Chambers, 273-277, Narsi Natha Street, Mumbai - 400009
Tel. No. : 2375 2321 / 1375 2322 / 2370 2136 / 2375 9893
SWIFT : UBININBBBZ, Telex : 011-73099

APPENDIX IV [Rule - 8 (1)]

POSSESSION NOTICE

(For immovable Property)

Whereas:

The undersigned being the Authorised officer of the **Union Bank of India,** Bhat Bazar Branch, under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002) and in exercise of the powers conferred under Section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued a demand notice dated **06/02/2015** calling upon the borrower **M/s. Bhikhabhai Gowardhandas & Co.** to repay the amount mentioned in the notice being **Rs. 15,33,99,962.10 (Rupees Fifteen Crore Thirty Three Lakh Ninety Nine Thousand Nine Hundred Sixty Two and Paise Ten only)** and interest thereon within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken Physical Possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under Section 13(4) of the said Act read with rule 8 of the Security Interest Enforcement) Rules 2002 on this **11th day of March, of the year 2019.**

The Borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of Union Bank of India, Bhat Bazar Branch for an amount of **Rs. 15,33,99,962.10 as on 31/01/2015** and further interest thereon.

The borrower's attention is invited to the provisions of Sub-Section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

Description of Immovable Property

Flat No. 002-A, Palace Shiv Sagar, Tilak Nagar, Chembur, Mumbai - 400089.

Sd/-
Date: 11/03/2019 **Authorized Officer**
Place: Mumbai **Union Bank of India**

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India
अच्छे लोग, अच्छा बैंक Good people to bank with

Bhat Bazar Branch
Anant Deep Chambers, 273-277, Narsi Natha Street, Mumbai - 400009
Tel. No. : 2375 2321 / 1375 2322 / 2370 2136 / 2375 9893
SWIFT : UBININBBBZ, Telex : 011-73099

APPENDIX IV [Rule - 8 (1)]

POSSESSION NOTICE

(For immovable Property)

Whereas:

The undersigned being the Authorised officer of the **Union Bank of India,** Bhat Bazar Branch, under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002) and in exercise of the powers conferred under Section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued a demand notice dated **06/02/2015** calling upon the borrower **M/s. Bhikhabhai Gowardhandas & Co.** to repay the amount mentioned in the notice being **Rs. 15,33,99,962.10 (Rupees Fifteen Crore Thirty Three Lakh Ninety Nine Thousand Nine Hundred Sixty Two and Paise Ten only)** and interest thereon within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken Physical Possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under Section 13(4) of the said Act read with rule 8 of the Security Interest Enforcement) Rules 2002 on this **11th day of March, of the year 2019.**

The Borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of Union Bank of India, Bhat Bazar Branch for an amount of **Rs. 15,33,99,962.10 as on 31/01/2015** and further interest thereon.

The borrower's attention is invited to the provisions of Sub-Section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

Description of Immovable Property

Flat No. 202, Swastik Value Heights, Plot No. Ndr-23, CTS No. 26, Off M. G. Road, Chembur, Mumbai - 400071.

Sd/-
Date: 11/03/2019 **Authorized Officer**
Place: Mumbai **Union Bank of India**

ऑयल इंडिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
Oil India Limited
(A Government of India Enterprise)

CIN: L11101AS1959GOI001148
Registered Office: Duliajan, Distt. Dibrugarh, Assam - 786 602, India
Corporate Office: Plot No. 19, Sector 16A, Noida - 201 301, Uttar Pradesh, India
Contact Person: Shri S. K. Senapati, Company Secretary and Compliance Officer
Tel: +91 (120) 241 9000 | **Fax:** +91 (120) 248 8310
Email: complianceofficer@oilindia.in | **Website:** www.oil-india.com

POST BUYBACK PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR THE ATTENTION OF EQUITY SHAREHOLDERS/BENEFICIAL OWNERS OF EQUITY SHARES OF OIL INDIA LIMITED

This post buyback public announcement (the "Post Buyback Public Announcement") is being made pursuant to the provisions of Regulation 24(vi) of the Securities and Exchange Board of India (Buy Back of Securities) Regulations, 2018 (the "Buyback Regulations"). This Post Buyback Public Announcement should be read in conjunction with the Public Announcement dated November 20, 2018 which was published on November 21, 2018 (the "Public Announcement") and the Letter of Offer dated February 5, 2019 (the "Letter of Offer"). The terms used but not defined in this Post Buyback Public Announcement shall have the same meaning as assigned to such terms in the Public Announcement and the Letter of Offer.

1. THE BUYBACK OFFER

1.1 Oil India Limited (the "**Company**") had announced the Buyback of not exceeding 5,04,98,717 (Five Crore Four Lakhs Ninety Eight Thousand Seven Hundred and Seventeen) fully paid-up equity shares of face value of ₹ 10 each ("**Equity Shares**") from all the equity shareholders/beneficial owners of Equity Shares as on the record date (i.e. Monday, December 3, 2018), on a proportionate basis, through the "**Tender Offer**" route at a price of ₹ 215 (Rupees Two Hundred and Fifteen only) per Equity Share payable in cash for an aggregate consideration not exceeding ₹ 10,85,72,24,155 (Rupees One Thousand Eighty Five Crore Seventy Two Lakhs Twenty Four Thousand One Hundred and Fifty Five only) ("**Buyback Offer Size**"). The Buyback Offer Size represents 5.00% and 5.01% of the aggregate of the fully paid-up equity share capital and free reserves as per the audited standalone and consolidated financial statements of the Company for the financial year ended March 31, 2018, respectively (the last audited financial statements available as on the date of the Board Meeting approving the Buyback) and is within the statutory limits of 10% of the aggregate of the fully paid-up equity share capital and free reserves as per standalone audited financial statements of the Company as per the provisions of the Companies Act, 2013 and the Buyback Regulations. The number of Equity Shares bought back in the Buyback constitutes 4.66% of the post Buyback equity share capital of the Company.

1.2. The Company has adopted Tender Offer route for the purpose of Buyback. The Buyback was implemented using the "Mechanism for acquisition of shares through Stock Exchange" notified by SEBI vide circular CIR/CFD/POLICYCELL/1/2015 dated April 13, 2015 read with the circular CFD/DCR2/CIR/P/2016/131 dated December 9, 2016, as may be amended from time to time ("**SEBI Circulars**"), notice number 20170202-34 dated February 2, 2017 from BSE and following the procedure prescribed in the Companies Act, 2013 and the Buyback Regulations.

1.3 The Buyback Offer opened on Friday, February 15, 2019 and closed on Friday, March 1, 2019.

2. DETAILS OF BUYBACK

2.1. The total number of Equity Shares bought back under the Buyback Offer are 5,04,98,717 (Five Crore Four Lakhs Ninety Eight Thousand Seven Hundred and Seventeen) Equity Shares at a price of ₹ 215 (Rupees Two Hundred and Fifteen only) per Equity Share.

2.2 The total amount utilized in the Buyback of Equity Shares is ₹ 10,85,72,24,155 (Rupees One Thousand Eighty Five Crore Seventy Two Lakhs Twenty Four Thousand One Hundred and Fifty Five Only) excluding filing fees payable to the SEBI, Stock Exchanges fees, advisors fees, turnover charges, public announcement publication expenses, printing and dispatch expenses, transaction costs viz. brokerage, applicable taxes such as securities transaction tax, service tax, stamp duty, etc.

2.3 The Registrar to the Buyback i.e. Karvy Fintech Private Limited *(formerly KCPL Advisory Services Private Limited)* (the "**Registrar**") considered 26,421 valid bids for 9,34,15,649 (Nine Crore Thirty Four Lakhs Fifteen Thousand Six Hundred and Forty Nine only) Equity Shares in response to the Buyback, resulting in the subscription of approximately 1.85 times the maximum number of shares proposed to be bought back.

The details of valid bids received by the Registrar in the Buyback Offer are as follows:

Category of Investor	No. of Equity Shares reserved in Buyback	No. of Valid Bids	Total Equity Shares Validly tendered	% Response
General category	4,29,23,909	1,541	8,53,90,309	198.93
Reserved category	75,74,808	24,880	80,25,340	105.95
Total	**5,04,98,717**	**26,421**	**9,34,15,649**	**184.99**

2.4. All valid bids have been considered for the purpose of Acceptance in accordance with the Buyback Regulations and Paragraph 19 of the Letter of Offer. The communication of acceptance/rejection has been dispatched by the Registrar to respective Eligible Shareholders on Tuesday, March 12, 2019.

2.5 The settlement of all valid bids was completed by the Clearing Corporation on Tuesday, March 12, 2019. For Demat Equity Shares accepted under the Buyback, the Eligible Shareholder will receive funds payout in their settlement bank account from the Clearing Corporation and in case of physical shares, the Clearing Corporation will release the funds to the Shareholder Broker as per secondary market payout mechanism. If Eligible Shareholder bank account details were not available or if the funds transfer instruction were rejected by RBI/respective bank, due to any reason, then such funds were transferred to the concerned Shareholder Broker for onward transfer to their respective Eligible Shareholder.

2.6 Demat Equity Shares accepted under the Buyback have been transferred to the Company's demat escrow account on Tuesday, March 12, 2019. The unaccepted demat Equity Shares have been returned to respective Shareholder/Shareholder Brokers/custodians by the Clearing Corporation on Tuesday, March 12, 2019. For Equity Shares tendered in physical form, the share certificates in respect of unaccepted Equity Shares are being dispatched to the registered address of the respective Eligible Shareholders by the Registrar/Company.

2.7 The extinguishment of 5,04,98,717 Equity Shares accepted under the Buyback comprising of 5,04,96,853 Equity Shares in dematerialized form and 1,864 Equity Shares in physical form, is currently under process and shall be completed by Tuesday, March 19, 2019. The Company and its directors accept full responsibility for the information contained in this Post Buyback Public Announcement and also accept responsibility for the obligations of the Company laid down under the Buyback Regulations.

3. CAPITAL STRUCTURE AND SHAREHOLDING PATTERN

3.1. The capital structure of the Company, pre and post Buyback Offer is as under:

(Equity Shares have a face value of ₹ 10 each)

Particulars	Pre Buyback		Post Buyback#	
	No. of Equity Shares	Amount (₹ in crore)	No. of Equity Shares	Amount (₹ in crore)
Authorized share capital	2,00,00,00,000	2,000.00	2,00,00,00,000	2,000.00
Issued, subscribed and paid up share capital	1,13,49,03,911	1,134.90	1,08,44,05,194	1,084.41

 # Subject to extinguishment of 5,04,98,717 Equity Shares

3.2. The details of the Shareholders/beneficial owners from whom Equity Shares exceeding 1% of the total Equity Shares bought back have been accepted for the Buyback Offer are as mentioned below:

S. No.	Name of the Shareholders	No. of Equity Shares accepted under the Buyback Offer	Equity Shares accepted as a % of total Equity Shares bought back	Equity Shares accepted as a % of total post Buyback Equity Shares
1.	The President of India acting through Ministry of Petroleum and Natural Gas, Government of India	3,35,63,696	66.46	3.10
2.	ICICI Prudential Life Insurance Company Limited	15,23,319	3.02	0.14

3.3. The shareholding pattern of the Company pre-Buyback (as on Record Date i.e. Monday, December 3, 2018) and post Buyback, is as under:

Particulars	Pre Buyback		Post Buyback^*	
	No. of Equity Shares	% of the existing Equity Share Capital	No. of Equity Shares	% of the post Buyback Equity Share Capital
Promoter	75,05,48,332	66.13	68,36,64,235	63.05
Foreign Investors (including Non Resident Indians, FIIs, FPIs and Foreign Mutual Funds	4,86,53,006	4.29	40,07,40,959	36.95
Financial Institutions/Banks/Mutual Funds promoted by Banks/Institutions	16,51,47,990	14.55		
Other (public, public bodies corporate etc.)	17,05,54,583	15.03		
Total	**1,13,49,03,911**	**100.00**	**1,08,44,05,194**	**100.00**

^In addition to the acceptance of 3,35,63,696 Equity Shares from the Promoter in the Buyback Offer, the post-Buyback shareholding of the Promoter also takes into account the transfer by the Promoter of 3,33,20,401 Equity Shares in relation to the CPSE ETF Scheme to the account of Reliance Nippon Life Asset Management Limited on December 4, 2018.

**Subject to extinguishment of 5,04,98,717 Equity Shares.*

4. MANAGER TO THE BUYBACK OFFER

SBI Capital Markets Limited

SBI CAPITAL MARKETS LIMITED
202, Maker Tower E, Cuffe Parade, Mumbai 400 005
Contact person: Mr. Janardhan Wagle/Mr. Aditya Deshpande
Tel: +91 (22) 2217 8300; **Fax**: +91 (22) 2218 8322
Email: oilbuyback2018@sbicaps.com; **Website**: www.sbicaps.com
SEBI Registration Number: INM000003531
Validity Period: Permanent Registration
CIN: U99999MH1986PLC040298

5. DIRECTORS' RESPONSIBILITY

As per Regulation 24(i)(a) of the Buyback Regulations, the Board of Directors of the Company accept full responsibility for the information contained in this Post Buyback Public Announcement and confirm that the information in this Post Buyback Public Announcement contains true, factual and material information and does not contain any misleading information.

For and on behalf of the Board of Directors of
OIL INDIA LIMITED

Sd/-	Sd/-	Sd/-
(Shri Utpal Bora)	(Shri Pramod Kumar Sharma)	(Shri S. K. Senapati)
Chairman & Managing Director	Director (Operations)	Company Secretary and Compliance Officer
(DIN: 07567357)	(DIN: 07194463)	(FCS: 2898)

Date : March 13, 2019
Place : Noida

PRESSMAN

আজিৰ টুইট

'শুনি ভাল লাগিল যে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়েও মহাজোঁটৰপৰা মহা পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে। মই সকলো ভাৰতীয়কে অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে তেওঁলোকে ব্যাপক হাৰত ভোট দিয়ে আৰু নতুন প্ৰধানমন্ত্ৰী নিৰ্বাচন কৰে।'

সমাজবাদী পাৰ্টীৰ নেতা **অখিলেশ যাদৱ**

পুনৰ বিজেপিৰে মিত্ৰতাক লৈ সৰৱ তিনিচুকীয়া জিলা অসম উন্নতি সভা

তিনি অগপ নেতাই গেৰুৱা বসন পিন্ধক

জিলাৰ বাতৰি দিওঁতা

তিনিচুকীয়া, ১৩ মাৰ্চ ঃ 'অসমৰ জনসাধাৰণক প্ৰতাৰণা কৰা অসম গণ পৰিষদ দলৰ সভাপতি অতুল বৰাসহ অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰিত্ব লাভ কৰা বিধায়ক ফণীভূষণ চৌধুৰী আৰু কেশৱ মহন্তৰ যদি লাজ আছে, তেন্তে গেৰুৱা বসন পিন্ধক। অসমৰ ৰাইজে গঠন কৰা আঞ্চলিক দল অগপৰ মুখা পিন্ধি থাকিব নালাগে।'— এই মন্তব্য অসম উন্নতি সভাৰ তিনিচুকীয়া জিলা সমিতিৰ সভাপতি প্ৰমোদ কুমাৰ বৰাৰ। এটা বিবৃতিত বৰাই প্ৰকাশ কৰে যে অতুল বৰা, ফণীভূষণ চৌধুৰী, কেশৱ মহন্তৰ আঞ্চলিক দলটোত থকাৰ নৈতিক অধিকাৰ নাই। নাগৰিকত্ব (সংশোধনী) বিধেয়ক-২০১৬ বাতিলৰ দাবীত হোৱা প্ৰতিবাদৰ জোৱাৰ দেখি নাটকীয়ভাৱে ৯ পৃষ্ঠাত চাওক

ডিব্ৰুগড়ত নিৰ্দলীয় হৈ যুঁজত নামিব ইজৰাইল নন্দ

জিলাৰ বাতৰি দিওঁতা

তিনিচুকীয়া, ১৩ মাৰ্চ ঃ ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত নিৰ্দলীয়ভাৱে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ সাজু হৈছে শ্ৰমিক নেতা ইজৰাইল নন্দ। আদিবাসী নেচনেল পাৰ্টী অব্ আছাম চমুকৈ আনপাৰ সমৰ্থনত ডিব্ৰুগড় লোকসভা ৯ পৃষ্ঠাত চাওক

এক পলকত

পৰম্পৰা ভংগ

পৰম্পৰা ভংগ কৰি আৰু লিংগ সমতাৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰি কৰ্ণাটকৰ বিজয়াপুৰা জিলাৰ এহাল দৰা-কইনাই ইজনে সিজনৰ ডিঙিত মংগলসূত্ৰ পিন্ধালে। লগতে এই বিয়াত কন্যাদান, মুহূৰ্তম আৰু চাউলেৰে দৰা-কইনাক আশীৰ্বাদ দিয়াৰ পৰম্পৰাও ভংগ হ'ল। দ্বাদশ শতিকাৰ সমাজ সংস্কাৰক বাসৱন্নাৰ লিংগ সমতাৰ আদৰ্শ বজাই ৰাখি নানাটাৰাড় গাঁৱত অসবৰ্ণ সমূহীয়া বিবাহ অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু দৰাই কইনাক মংগলসূত্ৰ পিন্ধোৱাৰ পিছত কইনাসকলেও তেওঁলোকক মংগলসূত্ৰ পিন্ধায়।

ডকাইতৰ দয়া

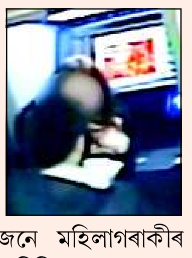

চীনৰ হেয়ুৱান চহৰত এজন ডকাইতে এটা এ টি এমত সোমাই ছুৰী দেখুৱাই এগৰাকী মহিলাৰপৰা ধন লুটিলে। কিন্তু আচৰিত ধৰণে আকৌ ২৫০০ য়ুৱান ধন ঘূৰাই দিলে। এ টি এমৰ চি চি টিভিৰ এই ফুটেজে ইণ্টাৰনেটত আলোড়ন সৃষ্টি কৰিছে। আচলতে ডকাইতজনে মহিলাগৰাকীৰ বেংকত কিমান ধন আছে চাব বিচাৰিছিল আৰু সেয়া চাওঁতে তাত এপইচাও নাই বুলি গম পাইছিল। তাৰ পিছতে ডকাইতজনৰ মন সলনি হয় আৰু ধনখিনি ঘূৰাই দিয়ে। ধন ঘূৰাই দিওঁতে ডকাইতজনৰ মিচিকিয়া হাঁহি আৰু শান্ত প্ৰস্থানে ইণ্টাৰনেটত তেওঁক চৰ্চিত কৰি তুলিছে।

নাগৰিকত্ব বিধেয়ক

অগপই স্থিতি সলালে নে বিজেপিয়ে ঃ বিশ্বাস

জিলাৰ বাতৰি দিওঁতা

বৰপেটা, ১৩ মাৰ্চ ঃ অগপ-বিজেপিয়ে একমাত্ৰ গাদী ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্‌মুহূৰ্তত নিৰ্বাচনী মিত্ৰতা ঘোষণা কৰাত আশ্চৰ্য প্ৰকাশ কৰিছে সদৌ অসম বাঙালী যুৱ-ছাত্ৰ ফেডাৰেচনৰ মুখ্য উপদেষ্টা সুকুমাৰ বিশ্বাসে। আজি এটা বিবৃতিত বিশ্বাসে কয় যে নাগৰিকত্ব (সংশোধনী) বিধেয়কক লৈ সম্পূৰ্ণ বিপৰীত মেৰুত অৱস্থান কৰি অহা দল দুটা নিশাটোৰ ভিতৰতে একগোট হোৱাৰ চৰ্ত কি সেয়া ৰাজ্যবাসীয়ে জানিবলৈ বিচাৰিছে। ৰাইজক পুনৰবাৰ অন্ধকাৰত ৰাখি নিৰ্বাচনী বৈতৰণী পাৰ কৰিব খুজিলে দুয়োটা দলেই তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব বুলি মত ব্যক্ত কৰে বিশ্বাসে। বিশ্বাসে আৰু কয় যে অগপই নাগৰিকত্ব (সংশোধনী) বিধেয়ক সমৰ্থন কৰিলে নে বিজেপিয়ে বিধেয়কৰ বিপক্ষে স্থিতি ল'লে, সেয়া স্পষ্ট কৰিব লাগে। অন্যথা দুয়োটা দলেই ক্ষতিৰ সন্মুখীন হোৱাটো খাটাং বুলিও মত প্ৰকাশ কৰিছে বিশ্বাসে।

অগপক ধিক্কাৰ দিলে শোণিতপুৰ নাগৰিক সমাজে

জিলাৰ বাতৰি দিওঁতা

তেজপুৰ, ১৩ মাৰ্চ ঃ 'অসমৰ ৰাইজৰ ৰক্ষাকৱচৰ ৰূপত এদিন ৰাইজে গঠন কৰা অসম গণ পৰিষদৰ নেতৃত্বই বিজেপিৰ সৈতে পুনৰ মিত্ৰতাত আবদ্ধ হোৱাটো অতি নিন্দনীয়। এই মিত্ৰতাৰে অগপ নেতৃত্বই নিজকে বিশ্বাসঘাতকৰূপে প্ৰতিপন্ন কৰি জাতিৰ ৰাজনৈতিক, সামাজিক, ভাষিক-সাংস্কৃতিক অধিকাৰ পতনৰ দ্বাৰ খুলি দিলে।' অগপ-বিজেপিৰ পুনৰ মিত্ৰতা সন্দৰ্ভত শোণিতপুৰ নাগৰিক সমাজে এইদৰে মন্তব্য কৰে। শোণিতপুৰ নাগৰিক সমাজৰ মুখ্য আহ্বায়ক পূৰ্ণেশ্বৰ নাথ, অঞ্জন গোস্বামী, পংকজ কুমাৰ নাথ, পুলিন ৯ পৃষ্ঠাত চাওক

বিক্ৰী জাননীৰ শুধৰণি/ বাতিল

ছাৰফায়েছি আইন ২০০২ৰ অধীনত বাতৰি কাকতত ২৭/০২/২০১৯ত প্ৰকাশিত ই-নিলাম বিক্ৰী জাননীৰ বিজ্ঞাপন সন্দৰ্ভত সকলো জনসাধাৰণক ইয়াৰ জৰিয়তে জনোৱা হয় যে ক্ৰমিক নং (৮) একাউণ্ট দীপা ভট্টাচাৰ্য্য, স্বামী- মৃত সত্যানন্দ ভট্টাচাৰ্য্য, শাখা- উলুবাৰীত উল্লিখিত সম্পত্তিবোৰ সন্দৰ্ভত বুজাবুজি/ উন্নীতকৰণ হোৱা হেতুকে ই-নিলাম বিক্ৰী জাননী নাকচ/বাতিল কৰা হ'ল।

কৰ্তৃত্বশীল বিষয়া
ইউনাইটেড বেংক অব ইণ্ডিয়া

ৰঞ্জিৎ বৰপূজাৰী বঁটা প্ৰদান কৰিব সাহিত্য সভাই

গুৱাহাটী, ১৩ মাৰ্চ ঃ অসমীয়া ভাষা সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে আত্মনিয়োগ কৰা অসমৰ বহুৰাষ্ট্ৰীয় ব্যৱসায়-প্ৰতিষ্ঠানক ভাষা শ্বহীদ ৰঞ্জিৎ বৰপূজাৰী বঁটা প্ৰদান কৰাৰ কথা আজি সাহিত্য সভাই ঘোষণা কৰিছে। প্ৰধান সম্পাদক পদুম ৰাজখোৱাই আজি এটা বিবৃতিত এই কথা ঘোষণা কৰি কয় যে যিসমূহ বহুৰাষ্ট্ৰীয় ব্যৱসায়-প্ৰতিষ্ঠানে অসমীয়া ভাষাৰ সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে আত্মনিয়োগ কৰিছে, তেওঁলোকক সন্মান প্ৰদানৰ কাৰণে এইবৰ্ষৰ পৰা ভাষা শ্বহীদ ৰঞ্জিৎ বৰপূজাৰী বঁটা প্ৰদানৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে।' বিজ্ঞপ্তিটোত লগতে কোৱা হৈছে যে ভাষা শ্বহীদগৰাকীৰ নামত দুবছৰৰ মূৰে মূৰে প্ৰদান কৰিবলগীয়া এই বঁটাটি এইবছৰৰ পৰাই প্ৰদান কৰা হ'ব। গতিকে, যিসমূহ প্ৰতিষ্ঠানে অসমীয়া ভাষা সম্প্ৰসাৰণৰ কাৰণে বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে, তেওঁলোকক নথি-পত্ৰসহ পদুম ৰাজখোৱা, প্ৰধান সম্পাদক, অসম সাহিত্য সভা, ভগৱতীপ্ৰসাদ বৰুৱা ভৱন, গুৱাহাটী-১ এই ঠিকনাত প্ৰতিবেদন পঠিয়াবলৈ সাহিত্য সভাই অনুৰোধ জনাইছে। বিবৃতিটোত কোৱা হৈছে যে যিসমূহ অনা-অসমীয়া বিষয়া-কৰ্মচাৰীয়ে অসমীয়া ভাষাৰ জ্ঞান আহৰণ কৰিব খোজে, তেওঁলোকক অসম সাহিত্য সভাই তিনিমহীয়া, ছয়মহীয়া, এবছৰীয়া পাঠ্যক্ৰমৰ জৰিয়তে অসমীয়া ভাষাৰ জ্ঞান প্ৰদান কৰিব। এইক্ষেত্ৰত অসমৰ বহুৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিষ্ঠানসমূহকো অনা-অসমীয়াক অসমীয়া ভাষা জ্ঞান প্ৰদানৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে সাহিত্য সভাই।

এবছু নীতি-আদৰ্শহীন ঃ হাগ্ৰামা

কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টি উদ্ধাৰৰ তৎপৰতা বি পি এফৰ

জিলাৰ বাতৰি দিওঁতা

কোকৰাঝাৰ, ১৩ মাৰ্চ ঃ কোকৰাঝাৰ লোকসভা (জনজাতীয়) সংসদীয় সমষ্টিক পুনৰ নিজৰ দখলত অনাৰ যুদ্ধং দেহী প্ৰস্তুতি লৈছে বি পি এফ দলে। আজি বি পি এফে কোকৰাঝাৰত এখন ৰুদ্ধদ্বাৰ বৈঠকত মিলিত হৈ এখন নিৰ্বাচন পৰিচালনা কেন্দ্ৰীয় সমিতি গঠন কৰে। মুৰব্বী হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে পৰিচালনা কৰা বৈঠকৰ অন্তত সংবাদ মাধ্যমক জনায় যে কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত এইবাৰ মূল যুঁজখন এবছুৰ ৯ পৃষ্ঠাত চাওক

বিজেপিয়ে বৰপেটা এৰিব অগপলৈ !

জিলাৰ বাতৰি দিওঁতা

বৰপেটা, ১৩ মাৰ্চ ঃ অৱশেষত সকলো জল্পনা-কল্পনাৰ ওৰ পেলাই অগপ-বিজেপিয়ে সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচনত মিত্ৰতা কৰি নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱাটো চূড়ান্ত হ'ল। প্ৰাপ্ত খবৰ অনুসৰি বিজেপিয়ে ৬ নং বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিটো মিত্ৰদল অগপক এৰি দিয়াৰ সম্ভাৱনা ৯ পৃষ্ঠাত চাওক

নাগৰিকত্ব বিধেয়কে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা ল'ব

নিৰ্বাচনক লৈ নলবাৰীৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ মত

ৰমেন কলিতা

নলবাৰী, ১৩ মাৰ্চ ঃ যোৱা কিছুদিন ধৰি ৰাজ্যৰ ৰাজনৈতিক পৰিবেশ উত্তপ্ত কৰি ৰখা নাগৰিকত্ব (সংশোধনী) বিধেয়ক ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত এইবাৰৰ লোকসভা নিৰ্বাচনে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই নিৰ্বাচন ৰাজ্যৰ বাবেও গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰিছে। আগন্তুক নিৰ্বাচনত এই বিধেয়কখনে ল'ব পৰা ভূমিকা সম্পৰ্কে নলবাৰীৰ বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী, শিক্ষাবিদ, ড° দীনমণি ভাগৱতীয়ে কয় যে ২০১৯ চনৰ সমাগত লোকসভাৰ নিৰ্বাচন উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ, বিশেষকৈ অসমৰ বাবে অতি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ হিচাপে চিহ্নিত হৈছে। নিৰ্বাচনৰ আগমুহূৰ্তত সমগ্ৰ উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ ৰাজনীতি নাগৰিকত্ব (সংশোধনী) বিধেয়কক লৈ উত্তাল হৈ পৰিছিল। ড° ভাগৱতীয়ে কয় যে নাগৰিকত্ব (সংশোধনী) বিধেয়কৰ জৰিয়তে উপকৃত হ'ব বিচৰা লোকসকল আৰু ইয়াৰ বিৰোধী লোকসকলৰ মাজত স্পষ্ট বিভাজনৰ সৃষ্টি হোৱাৰো সম্ভাৱনা আছে। তেওঁ ধাৰণা কৰা মতে, ৰাজনৈতিক দলৰ দলীয় আদৰ্শতকৈ গোষ্ঠীগত ৯ পৃষ্ঠাত চাওক

আনে ব্যৱহাৰ কৰিছে লিগেচী ডাটা

হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন দিচাংমুখৰ এটা পৰিয়াল

নিজা বাতৰি দিওঁতা

দিচাংমুখ, ১৩ মাৰ্চ ঃ অসমত এন আৰ চি প্ৰক্ৰিয়াৰ কাম চলি থকাৰ সময়ত শিৱসাগৰ ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত দিচাংমুখ নিৱাসী তথা শিক্ষক ৰামলাল শৰ্মাৰ পিতৃ প্ৰয়াত দধিৰাম শৰ্মাৰ নামত থকা লিগেচী ডাটা কোডটো ধেমাজীৰ চিলাপথাৰৰ এটা পৰিয়ালে ব্যৱহাৰ কৰাত শৰ্মাৰ পৰিয়ালটো হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হৈছে। ৰামলাল শৰ্মাৰ ৯ পৃষ্ঠাত চাওক

গ্ৰন্থ, ক্ষুদ্ৰ আলোচনী, পৰিপূৰিকা সংৰক্ষণৰ পদক্ষেপ

অসম সাহিত্য সভাৰ সৈতে ঐক্যবদ্ধ হ'ল ৰাজ্যিক সংগ্ৰহালয়

গুৱাহাটী, ১৩ মাৰ্চ ঃ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰকাশ হোৱাৰ পিছত প্ৰচাৰহীনভাৱে সিঁচৰতি হৈ থকা গ্ৰন্থ, ক্ষুদ্ৰ আলোচনী আৰু পৰিপূৰিকাসমূহ শৃংখলিতভাৱে নথিভুক্ত কৰি উপযুক্তভাৱে সংৰক্ষণ কৰাৰ প্ৰকল্প গ্ৰহণ কৰিছে অসম সাহিত্য সভাই। সাহিত্য সভাৰ ক্ষুদ্ৰ আলোচনী, শিক্ষানুষ্ঠান আৰু মুখপত্ৰ প্ৰদৰ্শনী আৰু প্ৰতিযোগিতা উপ-সমিতিৰ উদ্যোগত অসম ৰাজ্যিক সংগ্ৰহালয় সঞ্চালকালয়ৰ সহযোগত ৰূপায়ণ হ'ব লগা এই প্ৰকল্প প্ৰসংগত আজি সাহিত্য সভাৰ সভাপতি ড° পৰমানন্দ ৰাজবংশীৰ পৌৰোহিত্যত এখন বিশেষ সভা সাহিত্য সভাৰ গুৱাহাটীৰ ড° মহেন্দ্ৰ বৰা সোঁৱৰণী সভাকক্ষত অনুষ্ঠিত হয়। অসম ৰাজ্যিক সংগ্ৰহালয়ৰ সঞ্চালক ৰাই এছ উলুংলিংটন, প্ৰকাশন বিষয়া জিতেন কুমাৰ, যোৰহাট-ডিব্ৰুগড়-মাজুলীৰ জিলা ৯ পৃষ্ঠাত চাওক

ऑयल इंडिया लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम) Oil India Limited (A Government of India Enterprise)

CIN: L11101AS1959GOI001148
Registered Office: Duliajan, Distt. Dibrugarh, Assam - 786 602, India
Corporate Office: Plot No. 19, Sector 16A, Noida - 201 301, Uttar Pradesh, India
Contact Person: Shri S. K. Senapati, Company Secretary and Compliance Officer
Tel: +91 (120) 241 9000 | **Fax:** +91 (120) 248 8310
Email: complianceofficer@oilindia.in | **Website:** www.oil-india.com

POST BUYBACK PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR THE ATTENTION OF EQUITY SHAREHOLDERS/BENEFICIAL OWNERS OF EQUITY SHARES OF OIL INDIA LIMITED

This post buyback public announcement (the "Post Buyback Public Announcement") is being made pursuant to the provisions of Regulation 24(vi) of the Securities and Exchange Board of India (Buy Back of Securities) Regulations, 2018 (the "Buyback Regulations"). This Post Buyback Public Announcement should be read in conjunction with the Public Announcement dated November 20, 2018 which was published on November 21, 2018 (the "Public Announcement") and the Letter of Offer dated February 5, 2019 (the "Letter of Offer"). The terms used but not defined in this Post Buyback Public Announcement shall have the same meaning as assigned to such terms in the Public Announcement and the Letter of Offer.

1. THE BUYBACK OFFER

1.1 Oil India Limited (the "**Company**") had announced the Buyback of not exceeding 5,04,98,717 (Five Crore Four Lakhs Ninety Eight Thousand Seven Hundred and Seventeen) fully paid-up equity shares of face value of ₹ 10 each ("**Equity Shares**") from all the equity shareholders/beneficial owners of Equity Shares as on the record date (i.e. Monday, December 3, 2018), on a proportionate basis, through the "**Tender Offer**" route at a price of ₹ 215 (Rupees Two Hundred and Fifteen only) per Equity Share payable in cash for an aggregate consideration not exceeding ₹ 10,85,72,24,155 (Rupees One Thousand Eighty Five Crore Seventy Two Lakhs Twenty Four Thousand One Hundred and Fifty Five only) ("**Buyback Offer Size**"). The Buyback Offer Size represents 5.00% and 5.01% of the aggregate of the fully paid-up equity share capital and free reserves as per the audited standalone and consolidated financial statements of the Company for the financial year ended March 31, 2018, respectively (the last audited financial statements available as on the date of the Board Meeting approving the Buyback) and is within the statutory limits of 10% of the aggregate of the fully paid-up equity share capital and free reserves as per standalone audited financial statements of the Company as per the provisions of the Companies Act, 2013 and the Buyback Regulations. The number of Equity Shares bought back in the Buyback constitutes 4.66% of the post Buyback equity share capital of the Company.

1.2. The Company has adopted Tender Offer route for the purpose of Buyback. The Buyback was implemented using the "Mechanism for acquisition of shares through Stock Exchange" notified by SEBI vide circular CIR/CFD/POLICYCELL/1/2015 dated April 13, 2015 read with the circular CFD/DCR2/CIR/P/2016/131 dated December 9, 2016, as may be amended from time to time ("**SEBI Circulars**"), notice number 20170202-34 dated February 2, 2017 from BSE and following the procedure prescribed in the Companies Act, 2013 and the Buyback Regulations.

1.3 The Buyback Offer opened on Friday, February 15, 2019 and closed on Friday, March 1, 2019.

2. DETAILS OF BUYBACK

2.1. The total number of Equity Shares bought back under the Buyback Offer are 5,04,98,717 (Five Crore Four Lakhs Ninety Eight Thousand Seven Hundred and Seventeen) Equity Shares at a price of ₹ 215 (Rupees Two Hundred and Fifteen only) per Equity Share.

2.2 The total amount utilized in the Buyback of Equity Shares is ₹ 10,85,72,24,155 (Rupees One Thousand Eighty Five Crore Seventy Two Lakhs Twenty Four Thousand One Hundred and Fifty Five Only) excluding filing fees payable to the SEBI, Stock Exchanges fees, advisors fees, turnover charges, public announcement publication expenses, printing and dispatch expenses, transaction costs viz. brokerage, applicable taxes such as securities transaction tax, service tax, stamp duty, etc.

2.3 The Registrar to the Buyback i.e. Karvy Fintech Private Limited *(formerly KCPL Advisory Services Private Limited)* (the "**Registrar**") considered 26,421 valid bids for 9,34,15,649 (Nine Crore Thirty Four Lakhs Fifteen Thousand Six Hundred and Forty Nine only) Equity Shares in response to the Buyback, resulting in the subscription of approximately 1.85 times the maximum number of shares proposed to be bought back.

The details of valid bids received by the Registrar in the Buyback Offer are as follows:

Category of Investor	No. of Equity Shares reserved in Buyback	No. of Valid Bids	Total Equity Shares Validly tendered	% Response
General category	4,29,23,909	1,541	8,53,90,309	198.93
Reserved category	75,74,808	24,880	80,25,340	105.95
Total	**5,04,98,717**	**26,421**	**9,34,15,649**	**184.99**

2.4. All valid bids have been considered for the purpose of Acceptance in accordance with the Buyback Regulations and Paragraph 19 of the Letter of Offer. The communication of acceptance/rejection has been dispatched by the Registrar to respective Eligible Shareholders on Tuesday, March 12, 2019.

2.5 The settlement of all valid bids was completed by the Clearing Corporation on Tuesday, March 12, 2019. For Demat Equity Shares accepted under the Buyback, the Eligible Shareholder will receive funds payout in their settlement bank account from the Clearing Corporation and in case of physical shares, the Clearing Corporation will release the funds to the Shareholder Broker as per secondary market payout mechanism. If Eligible Shareholder bank account details were not available or if the funds transfer instruction were rejected by RBI/respective bank, due to any reason, then such funds were transferred to the concerned Shareholder Broker for onward transfer to their respective Eligible Shareholder.

2.6 Demat Equity Shares accepted under the Buyback have been transferred to the Company's demat escrow account on Tuesday, March 12, 2019. The unaccepted demat Equity Shares have been returned to respective Shareholder/Shareholder Brokers/custodians by the Clearing Corporation on Tuesday, March 12, 2019. For Equity Shares tendered in physical form, the share certificates in respect of unaccepted Equity Shares are being dispatched to the registered address of the respective Eligible Shareholders by the Registrar/Company.

2.7 The extinguishment of 5,04,98,717 Equity Shares accepted under the Buyback comprising of 5,04,96,853 Equity Shares in dematerialized form and 1,864 Equity Shares in physical form, is currently under process and shall be completed by Tuesday, March 19, 2019. The Company and its directors accept full responsibility for the information contained in this Post Buyback Public Announcement and also accept responsibility for the obligations of the Company laid down under the Buyback Regulations.

3. CAPITAL STRUCTURE AND SHAREHOLDING PATTERN

3.1. The capital structure of the Company, pre and post Buyback Offer is as under:

(Equity Shares have a face value of ₹10 each)

Particulars	Pre Buyback		Post Buyback#	
	No. of Equity Shares	Amount (₹ in crore)	No. of Equity Shares	Amount (₹ in crore)
Authorized share capital	2,00,00,00,000	2,000.00	2,00,00,00,000	2,000.00
Issued, subscribed and paid up share capital	1,13,49,03,911	1,134.90	1,08,44,05,194	1,084.41

 # Subject to extinguishment of 5,04,98,717 Equity Shares

3.2. The details of the Shareholders/beneficial owners from whom Equity Shares exceeding 1% of the total Equity Shares bought back have been accepted for the Buyback Offer are as mentioned below:

S. No.	Name of the Shareholders	No. of Equity Shares accepted under the Buyback Offer	Equity Shares accepted as a % of total Equity Shares bought back	Equity Shares accepted as a % of total post Buyback Equity Shares
1.	The President of India acting through Ministry of Petroleum and Natural Gas, Government of India	3,35,63,696	66.46	3.10
2.	ICICI Prudential Life Insurance Company Limited	15,23,319	3.02	0.14

3.3. The shareholding pattern of the Company pre-Buyback (as on Record Date i.e. Monday, December 3, 2018) and post Buyback, is as under:

Particulars	Pre Buyback		Post Buyback^*	
	No. of Equity Shares	% of the existing Equity Share Capital	No. of Equity Shares	% of the post Buyback Equity Share Capital
Promoter	75,05,48,332	66.13	68,36,64,235	63.05
Foreign Investors (including Non Resident Indians, FIIs, FPIs and Foreign Mutual Funds	4,86,53,006	4.29	40,07,40,959	36.95
Financial Institutions/Banks/Mutual Funds promoted by Banks/Institutions	16,51,47,990	14.55		
Other (public, public bodies corporate etc.)	17,05,54,583	15.03		
Total	**1,13,49,03,911**	**100.00**	**1,08,44,05,194**	**100.00**

^In addition to the acceptance of 3,35,63,696 Equity Shares from the Promoter in the Buyback Offer, the post-Buyback shareholding of the Promoter also takes into account the transfer by the Promoter of 3,33,20,401 Equity Shares in relation to the CPSE ETF Scheme to the account of Reliance Nippon Life Asset Management Limited on December 4, 2018.

**Subject to extinguishment of 5,04,98,717 Equity Shares.*

4. MANAGER TO THE BUYBACK OFFER

SBI Capital Markets Limited

SBI CAPITAL MARKETS LIMITED
202, Maker Tower E, Cuffe Parade, Mumbai 400 005
Contact person: Mr. Janardhan Wagle/Mr. Aditya Deshpande
Tel: +91 (22) 2217 8300; **Fax**: +91 (22) 2218 8322
Email: oilbuyback2018@sbicaps.com; **Website**: www.sbicaps.com
SEBI Registration Number: INM000003531
Validity Period: Permanent Registration
CIN: U99999MH1986PLC040298

5. DIRECTORS' RESPONSIBILITY

As per Regulation 24(i)(a) of the Buyback Regulations, the Board of Directors of the Company accept full responsibility for the information contained in this Post Buyback Public Announcement and confirm that the information in this Post Buyback Public Announcement contains true, factual and material information and does not contain any misleading information.

For and on behalf of the Board of Directors of
OIL INDIA LIMITED

Sd/-	Sd/-	Sd/-
(Shri Utpal Bora) Chairman & Managing Director (DIN: 07567357)	(Shri Pramod Kumar Sharma) Director (Operations) (DIN: 07194463)	(Shri S. K. Senapati) Company Secretary and Compliance Officer (FCS: 2898)

Date : March 13, 2019
Place : Noida

PRESSMAN